

न्यूज़ टुडे

विदेश मंत्रालय ने 'ओवरसीज मोबिलिटी (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025' के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित किए

इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के विदेशों में काम करने और वहां रहने से संबंधित कानूनों को एकीकृत एवं संशोधित करना है।

- इस विधेयक के तहत विदेश में रोजगार और कार्य-संबंधी उद्देश्यों के लिए प्रवासन की प्रक्रिया को सुरक्षित, कानूनी, सुव्यवस्थित व पारदर्शी बनाने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया गया है।
- यह विधेयक कानून बन जाने के बाद 1983 के इमिग्रेशन एक्ट का स्थान लेगा।
- वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव, कार्य के नए अवसरों के सृजन, और विदेश में रोजगार की तलाश के दौरान संकट में फंसने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का कानून आवश्यक हो गया है।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- ओवरसीज मोबिलिटी और कल्याण परिषद का गठन किया जाएगा। यह परिषद इस कानून के तहत शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेगी।
 - विदेश मंत्रालय का सचिव इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा।
- मोबिलिटी रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो प्रवासियों को सूचना, संसाधन एवं प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
- एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापित की जा सकती है, जो नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेंगी।
- गैर-कानूनी प्रवासन और मानव तस्करी की समस्याओं से निपटने हेतु नीतियां बनाई जाएंगी और आवश्यक उपाय किए जाएंगे।
- ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसियों को मान्यता देने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, कुछ श्रेणियों के विदेशी नियोक्ताओं के लिए कुछ प्रक्रियाएं भी अनिवार्य की जाएंगी।
- ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए कम-से-कम पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए 'रोडमैप' जारी किया

भारत का तकनीकी क्षेत्र संभावित रोजगार ह्रास का सामना कर रहा है, लेकिन अगले 5 वर्षों में 4 मिलियन नई नौकरियां सृजित करने का अवसर भी है।

- यह व्यापक रोडमैप कार्य-कामगार-कार्यबल (Work-Worker-Workforce) के परिप्रेक्ष्य का उपयोग करता है। यह दर्शाता है कि भारत कैसे व्यवधान (disruption) को अवसर में बदल सकता है और दुनिया की AI वर्कफोर्स कैपिटल बन सकता है।

भारत के सामने AI से संबंधित 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां

- व्यापक रोजगार परिवर्तन का जोखिम: भारत में 60% से अधिक औपचारिक नौकरियां 2030 तक स्वचालन (automation) के प्रति संवेदनशील हैं।
- कौशल में अंतराल: भारतीय स्नातक अक्सर विशेष व अनुसंधान-गहन AI करिकुलम और पाठ्यक्रम को रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन (RAG) जैसी नई अवधारणाओं के अनुरूप रखने में पीछे रह जाते हैं।
- AI प्रतिभा आपूर्ति-मांग में अंतराल: AI प्रतिभा की आपूर्ति वर्तमान में मांग की केवल लगभग 50% है।

नीति आयोग द्वारा भारत के लिए सिफारिशें

- रणनीति और निरीक्षण को एकजुट करने तथा निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशों को लागू करने के लिए भारत को एक AI प्रतिभा मिशन (AI Talent Mission) स्थापित करना चाहिए।
 - AI को सभी स्तरों पर एकीकृत करना चाहिए यानी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक।
 - राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम शुरू करना चाहिए और मौजूदा कार्यबल के लिए लचीले AI मास्टर्स एवं डॉक्टरेट प्रोग्राम शुरू करने चाहिए।
 - शीर्ष AI शोधकर्ताओं को बनाए रखने के लिए आकर्षक अनुदान और वेतन की पेशकश करना, स्वायत्त AI उत्कृष्टता केंद्र (AI CoEs) स्थापित करना, एक समर्पित AI प्रतिभा वीजा पेश करना और स्टार्ट-अप पुनर्वास सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- AI प्रतिभा मिशन को इंडिया AI मिशन के सहयोग से काम करना चाहिए।
 - एक इंडिया ओपन-सोर्स AI कम्युनिटीज़ को परिचालन में लाना: उच्च-गुणवत्ता वाले डेटासेट्स, मॉडल्स और पारदर्शी बेंचमार्क की मेजबानी करने वाला एक केंद्रीय पोर्टल बनाना चाहिए।
 - एक फेडरेटेड नेशनल कंप्यूट एंड इनोवेशन ग्रिड को परिचालन में लाना चाहिए।

AI कार्य के तरीके को मौलिक रूप से प्रभावित कर रहा है, जो एक कामगार की भूमिका को बदल रहा है और अंततः पूरे कार्यबल को प्रभावित कर रहा है

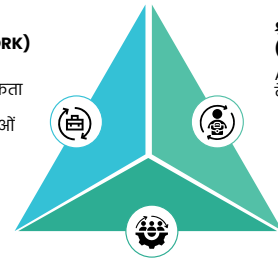
कार्य में परिवर्तन (Change in the WORK)

AI नियमित कार्यों को स्वचालित करेगा, उत्पादकता बढ़ाएगा और जटिल समस्या-समाधान क्षमताओं को बढ़ाएगा।

श्रमिक में परिवर्तन (Change in WORKER)

AI भूमिकाओं को नया आकार देगा, जिसमें:

- नए कौशल की आवश्यकता होगी,
- कुछ नौकरियां चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएंगी, और
- कुछ मामलों में पूरी तरह से नई नौकरियां पैदा होंगी।



कार्यबल में परिवर्तन (Change in WORKFORCE)

कार्यबल हाइब्रिड हो जाएगा, जिसमें AI और मानव एक टीम के रूप में कार्य करेंगे।

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नजर

- भारत ने काबुल स्थित अपने “तकनीकी मिशन” को ‘पूर्ण दूतावास’ का दर्जा देने की घोषणा की।
- भारत ने तालिबान को नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में अपने राजनयिक नियुक्त करने की अनुमति दी।
 - गौरतलब है कि अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था।
 - जून 2022 में, भारत ने “तकनीकी टीम” को तैनात कर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति फिर से दर्ज कराई थी।
- दोनों देशों ने सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की।
- अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग किसी भी अन्य देश के खिलाफ कोई गतिविधि चलाने के लिए नहीं किया जाएगा।
- भारत-अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की गई।
 - अफगानिस्तान ने भारतीय कंपनियों को अपने खनन क्षेत्र में अवसरों की खोज करने के लिए आमंत्रित किया।

तालिबान के साथ भारत के हालिया संपर्क के कारण

- अपने राष्ट्रीय हितों को साधना और सुरक्षा चिंताओं को दूर करना, ताकि अफगानिस्तान से संचालित आतंकवादी संगठनों पर अंकुश लगाया जा सके।
 - पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना।
 - पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध बिगड़ने के कारण उत्पन्न भूराजनीतिक बदलावों तथा व्यावहारिक राजनीति (रियल पॉलिटिक्स) को ध्यान में रखना।
 - अफगानिस्तान में क्षमता निर्माण और मानवतावादी पहलों के माध्यम से सद्भाव एवं विश्वास का निर्माण करना।
- भारत-अफगानिस्तान संबंधों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां
- तालिबान की शासन व्यवस्था निरंकुश है, जो विशेष रूप से महिलाओं के मानवाधिकारों की अनदेखी करती है।
 - तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक राजनयिक मान्यता नहीं मिली है।

सरकार ने “ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य” नियम अधिसूचित किए

कानूनी रूप से बाध्यकारी पहला GEI लक्ष्य नियम, 2025 चार उच्च-उत्सर्जन क्षेत्रों, अर्थात् एल्युमीनियम, सीमेंट, लुगदी व कागज और क्लोर-क्षार (chlor-alkali) को लक्षित करता है।

GEI, उत्पाद की प्रति इकाई पर उत्पन्न होने वाली GHGs की मात्रा है। उदाहरण के लिए- सीमेंट या एल्युमिनियम जैसे उत्पाद के प्रति टन के उत्पादन में मुक्त गैसों। नियम क्या हैं?

- किसके तहत जारी किए गए: कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS), 2023 के अनुपालन तंत्र के तहत।
- अनुपालन लागू करने वाला निकाय: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)।
- उद्देश्य: कार्बन-गहन क्षेत्रों में उत्पादन (उत्पाद के प्रति टन tCO₂e) के प्रति इकाई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को सुगम बनाना।

- अनुपालन करने वाली ऐसी संस्था, जो लक्ष्य से नीचे उत्सर्जन करती है, व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र अर्जित कर सकती है।
 - BEE कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
- गैर-अनुपालन संस्थाओं (Non-compliant entities) को अतिरिक्त प्रमाण-पत्र खरीदने होंगे या पर्यावरण मुआवजा देना होगा, जो उस अनुपालन वर्ष के लिए औसत कार्बन क्रेडिट मूल्य का दोगुना होगा।

महत्व

- बाजार-आधारित अनुपालन: अर्जित क्रेडिट्स का घरेलू कार्बन बाजार में व्यापार किया जा सकता है।
 - ये नियम CCTS, 2023 के तहत देश के घरेलू कार्बन बाजार को परिचालन में लाने में मदद करेंगे।
- पारदर्शिता: भारतीय कार्बन बाजार पोर्टल के तहत पंजीकरण और दस्तावेजीकरण।
- संधारणीयता के लिए राजस्व: पर्यावरण मुआवजा निधियां कार्बन बाजार बुनियादी ढांचे का समर्थन करती हैं।
- भारत के जलवायु लक्ष्यों का समर्थन: पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं का समर्थन करते हैं।



कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS), 2023 के बारे में

- उद्देश्य: भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के अनुरूप देश के भीतर GHG उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के लिए भारत का पहला घरेलू कार्बन बाजार विकसित करना।
- किसके तहत अधिसूचित: ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत।
- यह दो तंत्रों के तहत कार्बन बाजार स्थापित करता है:
 - अनुपालन तंत्र: ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए अनिवार्य कार्यक्रम, जहां सरकार GHG उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य निर्धारित करेगी।
 - ऑफसेट तंत्र: अनुपालन तंत्र के तहत कवर नहीं की गई संस्थाओं के लिए एक स्वैच्छिक परियोजना-आधारित तंत्र।

‘सा-धन’ (Sa-Dhan) ने सूक्ष्म-वित्त पर तिमाही रिपोर्ट जारी की

यह रिपोर्ट ‘भारत सूक्ष्म वित्त रिपोर्ट’ (Annual Bharat Microfinance Report) का हिस्सा है।

इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रक में ऋण चुकाने (Loan delinquencies) की दर में व्यापक गिरावट को उजागर किया गया है। इससे सूक्ष्म वित्त क्षेत्रक की पुनर्भुगतान प्रणाली पर दबाव बढ़ा है।

⊕ ऋण चुकाने में विफलता की मुख्य वजहों में ग्रामीण आर्थिक संकट, मौसम की वजह से नुकसान, वित्तीय साक्षरता की कमी आदि शामिल हैं।

भारत में सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रक

परिभाषा: सूक्ष्म-वित्त यानी माइक्रोफाइनेंस उन बैंकिंग सेवाओं को कहा जाता है, जो कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को ऋण प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं। इन व्यक्तियों या समूहों को आम तौर पर पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से ऋण नहीं मिल पाता है।

महत्त्व:

⊕ वित्तीय समावेशन में सहायक: ये संस्थाएं वंचित वर्गों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ती हैं।

⊕ ग्रामीणों को वित्तीय सेवा प्रदान करती हैं: सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं के 71% ग्राहक ग्रामीण हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म-वित्त ऋण प्रदाता संस्थाएं (MLIs) अविकसित ग्रामीण आबादी तक पहुंचने में सफल रही हैं।

⊕ महिलाओं के सशक्तीकरण में योगदान: ये संस्थाएं महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ऋण प्रदान करती हैं। इन SHGs ने सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने में अहम भूमिका निभाई है।

• गौरतलब है कि बैंकों से जुड़े 88% SHGs का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है।

सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं के समक्ष मुख्य चुनौतियां

⊕ परिसंपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट: विगत वर्ष की तुलना में जोखिम वाले पोर्टफोलियो (PAR) सभी श्रेणियों में बढ़त हो गए हैं। यह स्थिति वितरित ऋण से जुड़े जोखिम का संकेत देती है।

⊕ राज्यवार ऋण-चुकाने में विफलता की स्थिति: बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। बिहार में न केवल बकाया ऋण की राशि सबसे अधिक थी, बल्कि डिफॉल्ट दर भी सबसे ऊंची थी।

⊕ संचालन और वित्तीय चुनौतियां:

• ग्राहक और स्टाफ को जोड़े रखने में कठिनाई: सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं को अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को अपने साथ जोड़े रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

• कॉस्ट ऑफ फंड्स में वृद्धि: सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रक के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़कर 11.33% हो गया है। इसमें भी लघु सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं को सबसे अधिक लागत झेलनी पड़ी।

» ‘कॉस्ट ऑफ फंड्स’ से तात्पर्य उस लागत से है, जिसका बैंक और वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को उधार देने के लिए फंड प्राप्त करने हेतु भुगतान करते हैं।

• लाभप्रदता में गिरावट: 1% से कम की ‘इक़्ति पर रिटर्न (RoE)’ की रिपोर्ट करने वाली सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं की संख्या में उच्च वृद्धि दर्ज की गई है।

दीर्घकालिक संवृद्धि के लिए उपाय

सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रक की दीर्घकालिक संवृद्धि निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेगी:

⊕ ग्राहकों की ऋण चुकाने की क्षमता का बेहतर आकलन करना,

⊕ डिजिटल तकनीक अपनाना,

⊕ नीतिगत उपाय करना,

⊕ जिम्मेदारी से ऋण वितरण करना, और

⊕ ऋण-वसूली में सुधार करना।

सरकार द्वारा सूक्ष्म-वित्त को सशक्त करने के लिए उठाए गए कदम

➤ स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंक कार्यक्रम: इसका उद्देश्य SHGs के लिए ऋण वितरण बढ़ाना और SHGs द्वारा इन ऋणों का उपयोग गैर-आयसृजन गतिविधियों की बजाय उत्पादन आधारित गतिविधियों में करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

➤ प्रधान मंत्री मुद्रा योजना: यह योजना लघु व्यवसायों को बिना कुछ गिरवी रखे सूक्ष्म ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है।

➤ नाबार्ड द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता: नाबार्ड (NABARD) अपनी दीर्घकालिक पुनर्वित्त सुविधा (Long-Term Refinance Facility) के तहत लघु-वित्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

अन्य सुर्खियां



सिद्धी आदिवासी समुदाय

सिद्धी आदिवासी समुदाय एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) है। इसने 72 प्रतिशत से अधिक की साक्षरता दर हासिल की है।

सिद्धी आदिवासी समुदाय के बारे में

➤ इन्हें हब्बी या बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अप्रौकी-भारतीय आदिवासी समुदाय है, जिनके बारे में माना जाता है कि ये पूर्वी अप्रौका से प्रवास करके आए थे।

➤ अवस्थिति: भारत का पश्चिमी तट, अर्थात् गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र।

➤ व्यवसाय: पारंपरिक रूप से शिकारी और संग्राहक थे; अब अधिकांशतः कृषि मजदूर और दिहाड़ी मजदूर हैं।

➤ ऐसा माना जाता है कि वे पहली बार 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के साथ तथा 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों और अंग्रेजों के साथ, ज़्यादातर गुलामों के रूप में भारत आए थे।

➤ वर्तमान में, ये केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।



सावलकोट जल-विद्युत परियोजना

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की शीर्ष समिति ने सावलकोट जल-विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान कर दी है।

सावलकोट जल-विद्युत परियोजना के बारे में

➤ यह 1,856 मेगावाट क्षमता वाली ‘रन-ऑफ-द-रिवर’ जल-विद्युत परियोजना है।

➤ यह परियोजना चेनाब नदी पर केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रामबन एवं उधमपुर जिलों में प्रस्तावित है।

⊕ ‘रन-ऑफ-द-रिवर’ परियोजना बिजली उत्पादन के लिए नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करती है। इस तरह की परियोजना में बहुत कम जल भंडारण की आवश्यकता होती है या बिल्कुल नहीं होती।

➤ भारत द्वारा सिंधु जल संधि (IWT) के निलंबन के बाद पहली बार सिंधु नदी तंत्र पर किसी बड़ी जल-विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है।



राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM)

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने तीन बड़े बंदरगाहों (महापत्तनों) को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के तहत "ग्रीन हाइड्रोजन हब" के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की।

- 'ग्रीन हाइड्रोजन हब' के रूप में मान्यता प्राप्त बंदरगाह हैं:
 - ⊕ दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण (गुजरात);
 - ⊕ वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट प्राधिकरण (तमिलनाडु); तथा
 - ⊕ पारादीप पोर्ट प्राधिकरण (ओडिशा)
- 'ग्रीन हाइड्रोजन हब' की मान्यता मिलने से इन बंदरगाहों में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी, हरित निवेश में वृद्धि होगी और स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियों में नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के बारे में

- घोषणा: जनवरी 2023 में की गई।
- उद्देश्य: भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके उप-उत्पादों या डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना।
- लक्ष्य: वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।



नोबेल शांति पुरस्कार 2025

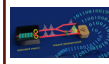
वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को देने की घोषणा की गई।

- यह पुरस्कार वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्यायसंगत एवं शांतिपूर्ण बदलाव हेतु मचाडो के संघर्ष के लिए दिया गया है।

नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में

- नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह पुरस्कार निम्नलिखित चार मुख्य क्षेत्रों में प्रयासों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता रहा है:
 - ⊕ शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण;
 - ⊕ शांति वार्ता;
 - ⊕ लोकतंत्र और मानवाधिकार;
 - ⊕ बेहतर संगठित और अधिक शांतिपूर्ण विश्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया कार्य।
- नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक:
 - ⊕ मदर टेरेसा (1979); तथा
 - ⊕ कैलाश सत्यार्थी (2014)

THE NOBEL PEACE PRIZE 2025



यादृच्छिक संख्याएं (Random Numbers)

रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने वास्तविक (True) यादृच्छिक संख्याएं प्राप्त करने और प्रमाणित करने के लिए नई क्वांटम तकनीक विकसित की।

यादृच्छिक संख्याएं क्या हैं?

- ये संख्याएं डिजिटल एन्क्रिप्शन, सत्यापन प्रणाली और साइबर सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं।
- वर्तमान प्रणालियां छद्म-यादृच्छिक संख्याओं (Pseudorandom numbers) का उपयोग करती हैं, जिन्हें एल्गोरिदम द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऐसी संख्याएं पूरी तरह से यादृच्छिक नहीं होतीं, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर की सहायता से इनका पूर्वानुमान किया जा सकता है।

वास्तविक यादृच्छिक संख्याएं क्या हैं?

- वास्तविक यादृच्छिकता (True Randomness) उन प्राकृतिक या भौतिक प्रक्रियाओं में देखी जाती है, जो प्राकृतिक रूप से अनिश्चित होती हैं, और किसी एल्गोरिदम से उत्पन्न नहीं होतीं।
 - ⊕ रेडियोएक्टिविटी और मौसम संबंधी घटनाएं प्रकृति में प्राप्त यादृच्छिक प्रक्रियाएं हैं।
- इनसे उत्पन्न संख्याएं पूर्णतः अप्रत्याशित एन्क्रिप्शन-की (Unpredictable Encryption Keys) बनाने में सक्षम होती हैं, जिससे डिजिटल प्रणालियां लगभग सुरक्षित बन सकती हैं।



बामियान बुद्ध

हाल ही में, बामियान बुद्ध सुर्खियों में थे।

बामियान बुद्ध के बारे में

- बामियान में बुद्ध की किसी स्मारक के आकार की दो प्रतिमाएं थीं, जिनकी ऊंचाई 115 और 174 फीट थी।
- अवस्थिति: मध्य अफगानिस्तान में बामियान घाटी की बलुआ पत्थर की चट्टानों में।
- अवधि: छठी शताब्दी में निर्मित।
- कलात्मक महत्त्व: ये प्रतिमाएं गांधार बौद्ध कला का उदाहरण प्रस्तुत करती थीं।
 - ⊕ मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार से निकटता से जुड़ी थीं।
- विध्वंस: 2001 में तालिबान द्वारा नष्ट कर दिया गया।
- यूनेस्को द्वारा मान्यता: बामियान घाटी को 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।



सुर्खियों में रहे स्थल



बारबाडोस (राजधानी: ब्रिजटाउन)

लोक सभा अध्यक्ष ने 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के अवसर पर बारबाडोस की नेशनल असेंबली में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल (IPD) का नेतृत्व किया।

भौगोलिक अवस्थिति

- अवस्थिति: यह दक्षिण-पूर्वी कैरेबियाई सागर (उत्तरी अटलांटिक महासागर) में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह वेनेजुएला के उत्तर-पूर्व में, लेसर एंटील्स के पास स्थित है।
 - ⊕ लेसर एंटील्स कैरेबियाई सागर में छोटे द्वीपों की एक लंबी चाप है, जो वर्जिन द्वीप समूह से ग्रेनाडा तक उत्तर-दक्षिण दिशा में फैली हुई है।

बारबाडोस कैरेबियाई समुदाय (CARICOM) और राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य है।

भौगोलिक विशेषताएं

- सबसे ऊँचा बिंदु: माउंट हिलबी।
- तलछट और प्रवाल निक्षेपों (sedimentary and coral deposits) से निर्मित।
- प्रवाल भित्तियों (coral reefs) से घिरा हुआ तथा कोई बड़ी नदी या झील नहीं है।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर